

The Hindu



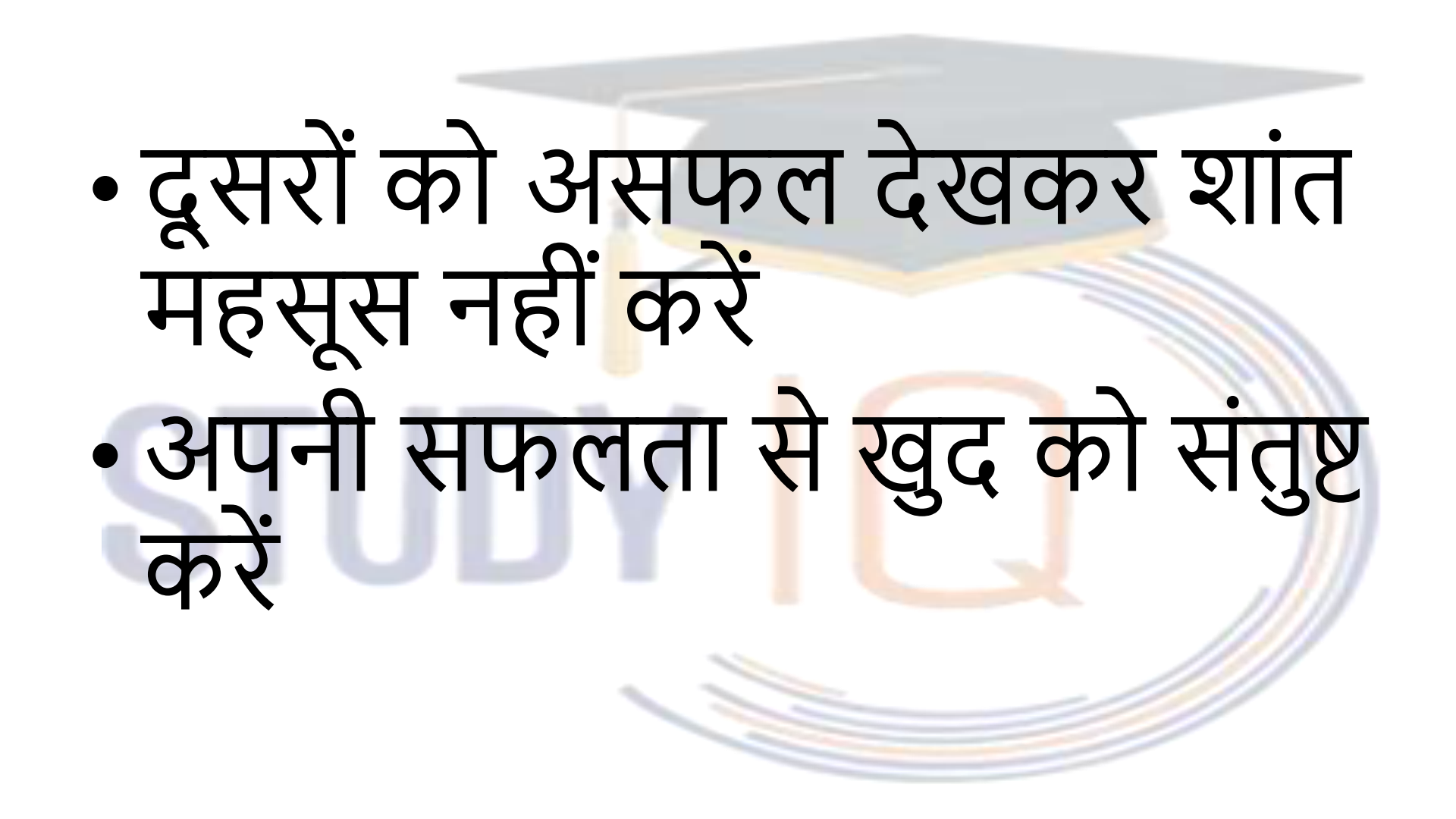
ANALYSIS IN ENGLISH



7TH FEBRUARY 2019

BY AMIT SAINI



- 
- दूसरों को असफल देखकर शांत महसूस नहीं करें
 - अपनी सफलता से खुद को संतुष्ट करें

शब्दावली

- Bewail
- Incinerate
- Insinuate
- Pedestal
- Ubiquitous
- Dissidence
- Astute



रोक और संतुलन

- 50% वीवीपीएटी पर्ची की गिनती की मांग बहुत अधिक है; ध्यान खामियों को खत्म करने पर होना चाहिए
- आम चुनावों के दौरान मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट टेल काउंटिंग प्रक्रिया में बदलाव की मांग करने के लिए विपक्षी दलों के मुख्यधारा के एक बड़े वर्ग के प्रतिनिधियों ने कागजी मतपत्रों की वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य परिवर्तन से चुनाव आयोग (ईसीआई) से मुलाकात की। पेपर बैलेट पर लौटना प्रतिगामी होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया, विपक्षी दलों के अपने कामकाज के बारे में शिकायतों के ढेर के बावजूद, पेपर आधारित मतदान पर एक बड़ा सुधार है। ईवीएम-छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है जैसा कि कुछ दलों द्वारा दावा किया गया है, और ईसीआई और ईवीएम निर्माताओं द्वारा स्थापित प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों को ईवीएम की शुरुआत के बाद से स्थिर रखा गया है। इसके बावजूद, चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी, ईवीएम के एक सहायक के रूप में वीवीपीएटी के कार्यान्वयन पर तैजी से नज़र रखी, जो मतदान के लिए एक पेपर टेल और बाद में ईवीएम की बैलेट यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत जनादेश के सत्यापन की अनुमति देता है। ईवीएम के साथ अब सभी विधानसभा और संसदीय चुनावों में वीवीपीएटी की तैनाती की जाती है। यह कार्यान्वयन कुछ गलतफहमियों के बिना नहीं हुआ है। वीवीपीएटी पर्ची के 50% की गिनती के लिए विपक्ष की मांग, जैसा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक यादृच्छिक रूप से चयनित बूथ में वीवीपीएटी पर्ची की वर्तमान प्रणाली के विपरीत है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।
- ईसीआई सुरक्षा उपायों को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, लेकिन वीवीपैट की गणना गलत अधिकारियों या निर्माताओं द्वारा संभावित “अदरूनी धोखाधड़ी” के बारे में किसी भी शेष संदेह को समाप्त कर सकती है।

- जबकि सभी पंचियों के आधे हिस्से को गिनने की मांग एक अति-प्रतिक्रिया है, क्योंकि बूथों के वैज्ञानिक और बेतरतीब ढंग से चुना गया नमूना इस प्रक्रिया के लिए एक उचित पर्याप्त सत्यापन है, सवाल यह है कि क्या प्रति निर्वाचन क्षेत्र में एक बूथ की गिनती एक सांख्यिकीय महत्वपूर्ण नियम है त्रुटियों को दूर करना।
- एक अधिक मजबूत नमूनाकरण तकनीक जो प्रत्येक राज्य और मतदाता मतदान के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के औसत आकार में कारक होती है, जिसमें कुछ राज्यों में एक से अधिक बूथ की गिनती शामिल है, एक बेहतर तरीका हो सकता है। ईसीआई की प्रतिक्रिया है कि वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उत्साहजनक होना चाहिए।
- वीवीपीएटी के साथ अन्य समस्या अधिक महत्वपूर्ण मशीन गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में संसदीय उपचुनाव और कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनावों के दौरान, वीवीपीएटी की गड़बड़ियां क्रमशः मशीन प्रतिस्थापन दरों में 20% और 4% तक बढ़ गईं। वीवीपीएटी मशीनों में ग्लिच मुख्य रूप से प्रिंट यूनिट में स्पिलिंग मुद्दों के कारण थे, जो चरम मौसम के प्रति संवेदनशील थे। कुछ हार्डवेयर संबंधी बदलाव पेश किए गए, जिसने हाल ही में पांच राज्यों में हुए चुनावों में अपने कामकाज में सुधार किया। वीवीपीएटी विफलताओं के कारण मशीन प्रतिस्थापन दरें छत्तीसगढ़ के लिए 1.89% पर आ गईं। बेहतर मशीनों की तैनाती से लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

हमें स्वास्थ्य सेवा खर्च में एक छलांग की आवश्यकता है

- भारत को न केवल देखभाल के एपिसोड पर दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है
- केंद्र और राज्य सरकारों ने हाल के दिनों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई नवाचारों की शुरुआत की है, जो भारत में सुधारों की अथक खोज के अनुरूप हैं।
- हालाँकि, सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना है, लेकिन स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का केवल 1.15-1.5% है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सरकार को अगले पांच साल या उससे अधिक के लिए हर साल स्वास्थ्य के लिए वित्त पोषण में 20-25% की वृद्धि करनी चाहिए।
- जबकि अंतरिम बजट किसानों और मध्यम वर्ग की जरूरतों के लिए उत्तरदायी है, यह स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं देता है।
- स्वास्थ्य सेवा का कुल आवंटन 61,398 करोड़ है। जबकि यह पिछले बजट से 7,000 करोड़ की वृद्धि है, कुल बजट का 2.2% होने के बाद से कोई शुद्ध वृद्धि नहीं हुई है, जो पिछले बजट के समान है।
- आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए आवंटित 6,400 करोड़ की वृद्धि लगभग बराबर है।

प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च

- 018 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 2009-10 में 21 621 से बढ़कर 2015-16 में in 1,112 हो गया। ये नवीनतम आधिकारिक नंबर उपलब्ध हैं, हालांकि 2018 में यह राशि लगभग 1,500 तक बढ़ सकती है। यह शक्ति समता खरीदने के लिए समायोजित होने पर \$ 20 या लगभग \$ 100 की राशि है। छह साल में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च दोगुना होने के बावजूद यह आंकड़ा अभी भी कम है।
- यह समझने के लिए कि अन्य देशों के साथ इसकी तुलना क्यों करें। अमेरिका प्रति वर्ष (2017 डेटा) स्वास्थ्य सेवा पर \$ 10,224 प्रति वर्ष खर्च करता है। दो बड़े लोकतंत्रों के बीच तुलना बता रही है: अमेरिकी स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 18% है, जबकि भारत अभी भी 1.5% है।
- बजट के संदर्भ में, अमेरिकी संघीय बजट में \$ 4.4 ट्रिलियन, मेडिकेयर और मेडिकाइड राशि पर \$ 1.04 ट्रिलियन पर खर्च करनी, जो कि बजट का 23.5% है। यू.एस. में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति संघीय बजट खर्च \$ 3,150 (\$ 1.04 ट्रिलियन / 330 मिलियन, जनसंख्या) है।

- भारत में, स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटन बजट का केवल 2.2% है। भारत में बजट में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च (458 (39 61,398 करोड़ / 134 करोड़) है, जो कि जनसंख्या है। (मेडिकेयर और मेडिकाइड सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ 'अनिवार्य खर्च' के अंतर्गत आते हैं।) क्रय शक्ति समता के लिए समायोजन, यह लगभग \$ 30, अमेरिका का सौवाँ हिस्सा है।
- माना जाता है कि अमेरिका में इस अपवाह स्वास्थ्य सेवा की लागत का अनुकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुलनीय विकसित देश अमेरिका की तुलना में प्रति व्यक्ति आधा खर्च करते हैं, अन्य ओईसीडी देशों में \$ 4,000- \$ 5,000 प्रति व्यक्ति खर्च की तुलना भारत के प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के निराशाजनक होने से नहीं है। अमेरिकी व्यय में वृद्धि की दर पिछले दशक में अन्य तुलनीय देशों के साथ धीमी हो गई है।
- अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई को 6,400 करोड़ रुपये का आवंटन स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करेगा, जो कि 67% के बड़े स्तर पर है। इसके बावजूद, भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति बजट खर्च दुनिया में सबसे कम है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

- पिछले साल, यह घोषणा की गई थी कि आयुष्मान भारत के तहत लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- इन केंद्रों का अधिदेश निवारक स्वास्थ्य, स्क्रीनिंग और बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं का समुदाय-आधारित प्रबंधन है। जनादेश में आधुनिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ स्वास्थ्य शिक्षा और समग्र कल्याण को शामिल किया जाना चाहिए। दोनों संचारी रोग रोकथाम के साथ-साथ गैर-संचारी रोग कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमानित 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के गैर-संचारी रोग कार्यक्रम 275 करोड़ से 175 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और नशामुक्ति कार्यक्रम का आवंटन केवल 65 करोड़ है, 2 करोड़ की कमी। प्रत्येक वेलनेस सेंटर के लिए आवंटन प्रति वर्ष 1 लाख से कम है। यह एक अल्प राशि है।
- इतिहास से पता चलता है कि जहां दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और संसाधन आवंटन है, निवेश पर समृद्ध रिटर्न संभव है। उदाहरण के लिए, एम्स, नई दिल्ली भारत में दशकों से संसाधन आवंटन के कारण ब्रांड मूल्य के साथ प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है। अकेले एम्स दिल्ली को अंतरिम बजट में लगभग 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल से 20% की वृद्धि है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक पर समान आवंटन की आवश्यकता है।

रोकथाम और इसका जीडीपी से संबंध

- नीति आयोग ने सार्वजनिक और निवारक स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए तम्बाकू, शराब और अस्वास्थ्यकर भोजन पर उच्च करों का प्रस्ताव किया है। इसने अंतरिम बजट में अपना रोस्ता नहीं खोजा है।
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में गैर-संचारी रोग निवारण रणनीतियों को निधि देने के लिए, तंबाकू और शराब पर कर जोड़ने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए। कैंसर की जांच और रोकथाम को कवर नहीं किया जाता है।
- निवारक ऑन्कोलॉजी, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए कोई संसाधन आवंटन नहीं है। क्रोनिक किडनी रोग की रोकथाम, जो 15-17% आबादी को प्रभावित करती है, उचित रूप से संबोधित नहीं की जाती है। स्पर्शमुख क्रोनिक किडनी रोग की प्रगतिशील प्रकृति बड़े पैमाने पर डायलिसिस और प्रत्यारोपण लागत के मामले में समुदाय के लिए भारी सामाजिक और आर्थिक बोझ की ओर जाता है जो केवल अगले दशक में एक घातीय वृद्धि को देखेगा और जब तक क्रोनिक किडनी रोग को कम नहीं करेगा तब तक टिकाऊ नहीं होगा। जब तक हम स्क्रीनिंग और रोकथाम के माध्यम से क्रोनिक किडनी रोग की घटनाओं और प्रसार को कम करते हैं।
- भारत में निवारक ऑन्कोलॉजी में ध्यान केंद्रित न होने के कारण, 70% से अधिक कैंसर का निदान III या IV चरणों में किया जाता है। विकसित देशों में रिवर्स सच है। नतीजतन, इलाज की दर कम है, मृत्यु दर अधिक है, और उन्नत कैंसर के उपचार में प्रारंभिक कैंसर के उपचार की तुलना में तीन-चार गुना अधिक है। मानक स्वास्थ्य बीमा पालिसी कैंसर को कवर करती है लेकिन उपचार लागत का केवल एक हिस्सा है। परिणामस्वरूप, या तो जेब से अधिक खर्च बढ़ जाता है या मरीज इलाज से बाहर हो जाते हैं।

- अकेले जीडीपी की वृद्धि स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि जीडीपी और स्वास्थ्य परिणामों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।
- हालांकि, स्वास्थ्य में सुधार जीडीपी के लिए सकारात्मक रूप से संबंधित है, क्योंकि एक स्वस्थ कार्यबल उत्पादकता में योगदान देता है। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि निधियों को वर्तमान आवंटन से निवारक देखभाल तक पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। पीएमजेएवाई में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए 1,354 पैकेजों को गुणवत्ता से जोड़ा जाना चाहिए। विभिन्न रोगों के लिए, एक निर्धारित समयावधि में रोग प्रबंधन के लिए आवंटन का पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए, न कि केवल देखभाल के प्रकरणों के लिए। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र बनाया जाना चाहिए, जैसे रक्षा। चूंकि यूनिवर्सल हेल्थकेयर में एक प्रमुख नवाचार को रोल आउट किया जा रहा है, इसलिए इसे फंडिंग में एक क्वॉंटम छलांग के साथ मेल खाना चाहिए। यदि हम राष्ट्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अधिक निवेश करते हैं तो ही जीडीपी में समान वृद्धि होगी।

गुणवत्ता की कीमत पर

- विज्ञान पत्रिकाओं और पेटेंट में प्रकाशन के लिए वित्तीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय समस्याओं से भरा है
- अंतिम वृद्धि के चार साल बाद 30 जनवरी को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पीएचडी छात्रों के लिए फेलोशिप स्टाइपेंड में लगभग 25% की वृद्धि की। सरकार का कहना है कि समय-समय पर बढ़ोतरी की समीक्षा की जाएगी। चूंकि यह वृद्धि 80% की बढ़ोतरी से कम है, जो कि रिसर्च फेलो पिछले छह महीनों से मांगे कर रहे हैं, उन्होंने अपने विरोध को जारी रखने का फैसला किया है।
- सरकार “शोध अध्येताओं के प्रदर्शन को बढ़ाने और पहचानने के लिए वित्तीय और शैक्षणिक प्रोत्साहन” प्रदान करने की योजना भी बना रही है, जिसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2 फरवरी को दी गई समिति की सिफारिशों के अंश, प्रकाशन और पेटेंट के लिए दिए जाने वाले वित्तीय पुरस्कारों की एक झलक प्रदान करते हैं। जबकि तौर-तरीकों पर काम किया जाना बाकी है, लेकिन प्रकाशन के लिए वित्तीय पुरस्कार की पेशकश करना एक बुरा विचार है।

चिंता का कारण

- पुत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्रों के आधार पर पुरस्कार देना, और इस आधार पर प्रोत्साहन का निर्धारण करना कि कागज अंतरराष्ट्रीय या भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। चीन में, उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं को 2016 में प्रकृति और विज्ञान जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित एक एकल पेपर के लिए लगभग \$ 44,000 दिए गए थे।
- प्रकाशन के लिए पुरस्कार राशि की गणना करने के लिए पत्रिकाओं के प्रभाव कारक (एक पत्रिका के सापेक्ष महत्व के लिए एक प्रॉक्सी) का उपयोग किया गया था। इससे चीनी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनैतिक अनुसंधान प्रथाओं और धोखाधड़ी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यह भारत में भी हो सकता है, जिसका इस क्षेत्र में पहले से ही एक अज्ञात रिकॉर्ड है और वैज्ञानिक धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं को संबोधित करने के लिए कोई नोडल निकाय नहीं है।
- भारत में, एक अंतरराष्ट्रीय और भारतीय पत्रिका में प्रकाशित एक पत्र के लिए क्रमशः 50,000 और 20,000 के एक बार के वित्तीय पुरस्कार की सिफारिश की गई है।
- भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक और वर्तमान विज्ञान के पूर्व संपादक पी। बालाराम कहते हैं, यह एक "दिमाग की योजना" है। "जो कोई भी इसके साथ आया है वह वैज्ञानिक प्रकाशन के इतिहास से अनभिज्ञ है। वे अनुसंधान को नष्ट कर देंगे (इस योजना के साथ)।"
- यह याद रखने योग्य है कि यद्यपि अकादमिक प्रदर्शन संकेतक पेश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इरादा अच्छा था, फिर भी भारत से प्रकाशित होने वाली शिकारी पत्रिकाओं में स्पाइक के लिए एपीआई काफी हद तक जिम्मेदार थे। इस बात की बहुत कम गारंटी है कि प्रकाशन पर आधारित इनाम प्रणाली भारत में विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता में और गिरावट नहीं लाएगी।

- इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए अधिक से अधिक पुरस्कार देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं भारतीय लोगों की गुणवत्ता में समान रूप से श्रेष्ठ नहीं हैं। जबकि नेचर, साइंस, सेल और द लैसेट प्रतिष्ठित हैं, कई पत्रिकाएं हैं जो खराब गुणवत्ता की हैं। इसी तरह, कुछ भारतीय पत्रिकाएं कम प्रभाव कारक होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय लोगों से बेहतर हैं।
- प्रोफेसर बालाराम कहते हैं, "अगर भारतीय पत्रिकाओं को औसत या नीचे के औसत पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पत्रिकाओं की कुल गुणवत्ता कम होगी।" भारतीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले छात्रों को 60% कम वेतन देकर, सरकार अनजाने में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के बीच की खाई को चौड़ा कर देगी, जो लंबे समय में आत्म-विनाशकारी होगा।
- इसके अलावा, "भारतीय विज्ञान गहरी जड़ें, संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है - फैलोशिप में देरी हो जाती है और प्रोजेक्ट फंडिंग समय पर जारी नहीं की जाती है," गौतम मेनन, गणितीय विज्ञान संस्थान में कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञानी कहते हैं। उनका तर्क है कि सरकार को उदार अनुसंधान और कम बाधाओं के साथ अच्छे शोध को पुरस्कृत करना चाहिए। हर साल सैकड़ों पत्र प्रकाशित होने के साथ, यह बहस का मुद्दा है कि क्या सरकार ऐसे प्रोत्साहन प्रदान करने में सक्षम होगी जो अनुसंधान प्रयोगशालाओं को कथित तौर पर देरी के फंड संकट का सामना कर रहे हैं।

पेटेंट के लिए इनाम

- छात्रों को पेटेंट (भारतीय या अंतरराष्ट्रीय) प्राप्त करने पर 1,00,000 का प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव आपदा के लिए एक बड़ा नुस्खा है।
- जबकि पेटेंट प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, भारत में पेटेंट दाखिल करने के लिए 10,000-30,000 खर्च होते हैं। पेटेंट का मसौदा तैयार करने में अतिरिक्त 50,000 का खर्च आता है और वार्षिक नवीकरण शुल्क भी लगता है। इसके अलावा, सभी पेटेंट उत्पादों में नहीं बदलते हैं।
- विज्ञान मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की गलतियों से नहीं सीखा है। 2016 के अंत में, सीएसआईआर ने अपने 38 प्रयोगशालाओं को भारतीय और विदेशी पेटेंटों की अंधाधुंध दाखिल को रोकने के निर्देश दिए। तब सीएसआईआर के महानिदेशक गिरीश सोहनी ने कहा था कि अधिकांश पेटेंट बायोडेटा पेटेंट हैं "और बिना किसी तकनीकी-वाणिज्यिक और कानूनी मूल्यांकन के दाखिल करने के लिए दायर किए गए थे"। ऐसे परिदृश्य में, पेटेंट-फाइलिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन केवल समस्या को बढ़ाएगा।

एक चिंताजनक दृष्टिकोण

- क्या आयुष्मान भारत सहकारी संघवाद की भावना को ठेस पहुंचाएगा?
- पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली और ओडिशा के आयुष्मान भारत में शामिल नहीं होने से यह सवाल उठता है कि क्या यह योजना सहकारी संघवाद के विचार को प्रभावित कर रही है। संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों को अस्पताल सेवाओं के लिए जिम्मेदार बनाती है। चिकित्सा राहत पाने वालों को वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की अपनी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) नामक एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया, जो प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख की राशि के लिए है।
- आयुष्मान भारत को मौजूदा राज्य नामों से जोड़ने की जिद और 7.5 करोड़ परिवारों के लिए एक व्यक्तिगत पत्र के तिरस्कार के साथ केवल प्रधानमंत्री की तस्वीर को वर्तमान प्रशासन के लिए पूरे क्रेडिट का प्रयास करने के रूप में देखा गया था, हालांकि राज्य सरकारें समान भागीदार हैं - 40 इस योजना का%, इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करने और लाभार्थियों की संख्या को दोगुना करने का है।

- यह देखते हुए कि केंद्र सरकार वित्त आयोग, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को धन हस्तांतरित करती है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) से एक संस्थागत वास्तुकला का निर्माण करने, प्रक्रियाओं, लागतों का मानकीकरण करने और सभी आकड़ों को प्रभावी निगरानी बनाने के लिए अपेक्षित है।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवंटित धन के उचित उपयोग के लिए संसद और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति जवाबदेह है। लेकिन इस तरह के मानकीकरण से नवाचार को प्रभावित किया जा सकता है और महंगी संरचनाएं हो सकती हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों, वरीयताओं और लागत प्रभावी समाधानों को समायोजित नहीं कर सकती हैं। इसके बजाय, जब धन प्रदान किया जाता है, तो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधीन, राज्यों में कुछ नया करने की गुंजाइश होती है, उनके संदर्भ, संसाधन आधार, महामारी विज्ञान की स्थिति, विकास के स्तर को फिट करने के लिए डिज़ाइन, कुल स्वामित्व लेते हैं और परिणामों के लिए जवाबदेह होते हैं।
- एनएचए का दृष्टिकोण सर्वसम्मति से निर्मित नहीं होता है। इसके मॉडल में मूल्य निर्धारण सेवाओं, पूर्व-प्राधिकरणों, बिलों की जांच, शिकायत निवारण और निजी कंपनियों और तीसरे पक्ष के प्रशासकों की धोखाधड़ी का पता लगाने के महत्वपूर्ण कार्यों को आउटसोर्स करना शामिल है। यह वर्तमान लागत को 6% से 30% तक बढ़ा सकता है, जैसा कि यू.एस. की चिकित्सा योजना में देखा गया है।

ट्रम्प और उनके सेना प्रमुख

- अपने सभी कलह के लिए, कोई भी यह नहीं जानता है कि अमेरिकी वापसी के समय अराजकता का प्रबंधन कैसे किया जाता है
- यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे बुरे दुश्मन भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर निकलने सहित कई चुनाव अभियान विदेश नीति के वादों को पूरा किया है; ईरान परमाणु समझौते और ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी ने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित किया और सहयोगी देशों पर संयुक्त रक्षा के लिए अधिक भुगतान करने का दबाव डाला।
- आश्चर्य की बात यह है कि एक अन्य ट्रम्प अभियान ने 'अंतहीन युद्धों' को समाप्त करने और अमेरिकी सैनिकों को विदेश में वापस लाने के लिए, विशेष रूप से सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को वापस लाने के लिए, दोनों नागरिकों और सैन्य हलकों से निंदा और खुले या अप्रत्यक्ष बाधा से मुलाकात की है।

भीतर विरोध

- इस विरोध को कुछ उच्च-स्तरीय इस्तीफे जैसे कि रक्षा सचिव जेम्स मैटिस द्वारा चिह्नित किया गया है - जिसे मीडिया द्वारा नायक-शहीद का दर्जा दिया गया है - श्री ट्रम्प द्वारा सीरिया और लगभग 7,000 से कुछ 2,000 बलों को वापस लेने के निर्णय से उकसाया गया है, जो कि अफगानिस्तान से कुल संख्या का लगभग आधा है। श्री ट्रम्प के कदमों को अलगाववादी और यू.एस. के दुश्मनों के पक्ष में, विशेष रूप से रूस और ईरान की निंदा की जाती है।
- अफगानिस्तान के संबंध में, उनका विरोध यह महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि तालिबान के साथ सीधी बातचीत के लिए डांडाउन एक आवश्यक प्रस्तावना था। आपत्ति करने वाले यह भी कहते हैं कि इजरायल अधिक खतरे के संपर्क में है, एक कारण पक्षपातपूर्ण पक्षपात का आनंद लेना है। जनरल मैटिस ने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा है कि वह "क्योंकि आपके पास रक्षा सचिव का अधिकार है, जिसके विचार आपके साथ बेहतर संरेखित हैं।" यह आश्चर्यजनक है कि किसी भी गलत संरेखण का पता लगाने में उसे दो साल लग गए।
- विदेश में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव श्री ट्रम्प के आलोचकों को स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि 1961 में राष्ट्रपति डवाइट आइजनहावर द्वारा संदिग्ध अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक परिसर में अभी भी नागरिक अधिकार निहित है, और विश्व युद्ध के बाद से, अमेरिकी विदेश नीति पूरी तरह से सैन्यीकृत कर दिया गया है। हर अंतरराष्ट्रीय समस्या के लिए, वाशिंगटन के पास प्रतिबंधों के आवेदन और बल के खतरे या उपयोग की केवल दो प्रतिक्रियाएं हैं।

- श्री ट्रम्प को मुख्यधारा के मीडिया द्वारा अलगाववादी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, इस बात का सबूत है कि नव-साम्राज्यवादी भावना और ईश्वर द्वारा सैन्य आधिपत्य रखने का अधिकार पूरे अमेरिकी प्रतिष्ठान में गहरा है।
- इसलिए फ्रांसिस फुकुयामा की भविष्यवाणी भी है कि "मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु [है] पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण मानव सरकार के अंतिम रूप के रूप में।"
- एक बिकवाली के बारे में जोर देकर कहा कि श्री ट्रम्प केवल उस विश्व शक्ति के साथ संपर्क करने की इच्छा रखते हैं जो अमेरिका को उकसा सकती है, हालांकि हर पिछले अमेरिकी नेता ने दुनिया को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत की। यह विशेष वकील रॉबर्ट म्यूलर की रूसी मिलीभगत के बारे में, और अधिक दुनिया में अमेरिका की भूमिका की कल्पना के साथ करने के लिए कम है।
- न्यूयॉर्क टाइम्स ने "विश्व व्यवस्था के बारे में लिखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने 73 साल की नेतृत्व किया है", श्री ट्रम्प पर यह आरोप लगाते हुए कि "वैश्विक पदचिह्न को उस आदेश को एक साथ रखने की आवश्यकता है"। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल जैसे अनुपालन वाले यूरोपीय सहयोगियों द्वारा एक ही विषय को बेहद उत्सुकता से प्रतिध्वनित किया गया है, जिन्होंने जुलाई 2018 में कहा था कि श्री ट्रम्प के तहत यू.एस. को "आदेश देने" पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन किसका आदेश?

- श्री ट्रम्प ने यह दावा करने में गलत है कि अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) को नष्ट कर दिया, न केवल इसलिए कि इसके कुछ अवशेष बचे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिकी-गठबंधन विमानों ने कई हजार फीट से अध्यादेश गिरा दिया है और असंख्य नागरिकों को मार डाला है। प्रक्रिया, आईएस के खिलाफ वास्तविक लड़ाई पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्दा और असद सरकार, रूसियों, ईरानियों और हिजबुल्लाह द्वारा कहीं और की गई है। लगभग 2,000 के छोटे अमेरिकी दल कुर्दा को प्रशिक्षित करने और आपूर्ति करने, तुर्कों को विवश करने और एक शांति समझौते की दिशा में प्रगति को बाधित करने का काम करते हैं। कहीं और के रूप में, अमेरिकी अंतिम स्थानीय सैनिक तक लड़ने के लिए तैयार हैं। श्री ट्रम्प को ईरान पर एक कठिन लाइन पर कांग्रेस, मीडिया और सेना का समर्थन है - फिर से, एक अभियान का वादा - लेकिन पश्चिम एशिया में, श्री ट्रम्प ने सऊदी अरब जैसे सहयोगियों के लिए स्थानीय कार्रवाई को आउटसोर्स किया, यमन में इसकी आपराधिक गतिविधियाँ पर नज़र रखी और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या भी की।
- श्री ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया में, जवाबदेही, जिम्मेदारी और नागरिक निरीक्षण को छोड़ दिया जाता है, जबकि लोगों को वर्दी में और छाया में - सर्वव्यापी अमेरिकी खुफिया सेवाओं - बुलंद पेडस्टल्स पर उठाया जाता है, असंतोष को प्रोत्साहित करता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री ट्रम्प की घोषणाओं के कारण भयावह प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। जैसा कि मीडिया और कांग्रेस द्वारा मांग की गई है, यू.एस. नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने रूसी समकक्षों के साथ बैठकें रद्द कर दीं, और अंतरिक्ष में अमेरिका-रूस के सहयोग की समाप्ति संभावित है। पेंटागन अब रिपोर्ट करता है कि चीन "सैन्य और गैर-सैन्य साधनों" और पाकिस्तान, कंबोडिया और सैन्य ठिकानों द्वारा विस्तार चाहता है, जो अमेरिकी जनता ने कभी नहीं सुना है। पेंटागन ने निष्कर्ष निकाला है कि चीन "संभावित तीसरे पक्ष को पढ़ने, रोकने और हारने की क्षमता विकसित कर रहा है [यू.एस.] क्षेत्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप"। श्री ट्रम्प और उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोङ-उन के बीच एक दूसरे शिखर सम्मेलन के साथ, मीडिया दक्षिण कोरिया में किसी भी अमेरिकी-उत्तर कोरियाई डेटेंट के परिणामस्वरूप अमेरिकी सेना की किसी भी कमी के खिलाफ सावधानीपूर्वक चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल जोसेफ डनफोर्ड, यह अनुमान लगाने के लिए वर्जन करते हैं कि चीन "संभवतः 2025 तक हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है"।

ईरान के साथ अंतिम शब्द

- अंतिम बातचीत ईरान के साथ रहता है, जिसे श्री ट्रम्प और उनके घरेलू सहयोगियों द्वारा दुश्मन माना जाता है।
- जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने जनवरी में दावा किया था कि "जब अमेरिका पीछे हटता है, तो अराजकता अक्सर पीछा करती है", ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने ट्वीट करके कहा, "जब भी और जहाँ भी अमेरिका हस्तक्षेप करता है, अराजकता, दमन और नाराजगी का पालन करता है। कोई भी इसमें शामिल नहीं है।" संयुक्त राज्य अमेरिका सुन रहा है।

Gadkari launches highway, port projects in Odisha

'₹2.5 lakh cr. for infrastructure, but the State must cooperate'

PRESS TRUST OF INDIA
DHENKANAL (ODISHA)

Union Minister Nitin Gadkari on Wednesday launched a slew of highway and port projects worth ₹6,000 crore in Odisha and said another ₹2.5 lakh crore would be pumped in to boost the infrastructure here but the State must cooperate by expediting land acquisition process.

The Road Transport and Highways, Shipping and Water Resources Minister laid foundation for three National Highway projects worth ₹2,345 crore at Kamakhyanagar in Dhenkanal district of Odisha. These projects include four-laning of the Talcher-Kamakhyanagar section of NH-200/23, Kamakhyanagar-Duburi section of NH-200 and Duburi-Chandikhole section of NH-200, the officials said.

He also inaugurated a port project worth ₹431 crore and laid foundation for six others costing ₹3,206 crore at a function at Paradip in Jagatsinghpur district.

Stating that the length of National Highways in Odisha has more than doubled in



Union Ministers Nitin Gadkari and Dharmendra Pradhan.

• FILE PHOTO

the last four years from 4,632 km in 2014 to 9,426 km in 2018, Mr. Gadkari said the Centre was spending nearly ₹1 lakh crore on NH in the State. He added investments worth ₹2.5 lakh crore would be made soon to strengthen the State's transportation sector.

Speaking on infrastructure projects which are stuck due to issues like land acquisition, forest and environment clearances, the Union Minister said the State government should cooperate in addressing these issues.

Mr. Gadkari added that NH projects worth over ₹6,000 crore have been completed in the State. Several other projects worth

₹4,500 crore are scheduled for completion this year, he said.

The Minister announced that a 262 km-long waterway, combining Mahanadi and Brahmani rivers, will be developed from Kalinganagar to Dhamra via Paradip at a cost of ₹5,000 crore.

Speaking on the port-led industrialisation, Mr. Gadkari said 34 projects worth ₹20,000 crore have been identified for Odisha under Sagarmala. Among the projects launched was a multi-purpose berth for handling clean cargo for diversifying its freight profile. Its capacity is 5 MMTA at an estimated cost of ₹430.78 crore, officials said.





STUDY IQ